



**MESSAGE**

It gives me great pleasure to extend my warmest greetings to all our Passport Issuing Authorities in India and abroad on the occasion of the 14<sup>th</sup> Passport Seva Divas.

This day marks the historic anniversary of the enactment of the Passports Act of 1967. It is an annual opportunity for the Ministry of External Affairs to reaffirm our unwavering commitment to providing citizen-centric, transparent, and highly efficient passport-related services. Driven by the Prime Minister Shri. Narendra Modi ji's vision of "Minimum Government, Maximum Governance", the Passport Seva Programme has emerged as a shining exemplar of *Sushasan* and ease of living, serving as an example for building a *Viksit Bharat*.

Our efforts to integrate public services into a seamless digital ecosystem have achieved new milestones. I am delighted to highlight that last year, the Ministry operationalised the upgraded Passport Seva Programme (PSP V2.0) across our vast domestic network. Alongside this, we also reinforced the security and convenience of the Indian diaspora through the deployment of the Global Passport Seva Programme (GPSP V2.0) at our diplomatic missions and posts worldwide. This unified digital infrastructure guarantees that both domestic applicants and Indian nationals abroad have access to the cutting-edge digital ecosystem.

A defining feature of this technological shift is the successful rollout of chip-enabled e-Passports. Meeting international benchmarks, these travel documents enhance security and authentication for our citizens. By leveraging advanced technologies and secure integrations with systems like DigiLocker, we are making the application processing faster, more transparent, and user-friendly.

We continue to expand our infrastructure via an extensive network of 545 plus Passport Seva Kendras (PSKs) and Post Office Passport Seva Kendras (POPSKs). Complemented by the deployment of Passport Mobile Vans, we are actively bridging the last-mile connectivity gap. This brings reliable, flexible, and convenient services to the farthest corners and rural heartlands of our country. I am delighted to note that the annual passport issuance volume has surged to more than 138 lakh in FY 2025-26 compared to 83 lakh in FY 2013-14, a testament to Ministry's commitment towards meeting the aspirations of a globalising India.

I take this opportunity to commend the dedicated workforce of Ministry and the Central Passport Organisation for their tireless efforts and all our partners in the Passport Seva Programme including the Department of Posts, Police authorities, India Security Press Nashik and other service providers for their continued contribution.

Let us rededicate ourselves today to the guiding principle of Surakshit Passport, Sugam Seva, Sashakt Nagrik. Together, let us continue to innovate, simplify rules, and relentlessly strive toward setting a global standard in citizen-centric public service delivery.

  
(Dr. S. Jaishankar)

**June 24, 2026**



### संदेश

भारत तथा विदेशों में स्थित सभी पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकरणों को 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

यह दिवस 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के ऐतिहासिक अधिनियमन की वर्षगाँठ का प्रतीक है। यह हमारे लिए प्रतिवर्ष एक ऐसा अवसर है जब विदेश मंत्रालय नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी तथा अत्यंत दक्ष पासपोर्ट सेवाएँ प्रदान करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” की दृष्टि से प्रेरित पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम सुशासन और जीवन की सुगमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है तथा विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक आदर्श के रूप में कार्य करता है।

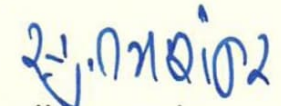
सार्वजनिक सेवाओं को एक निर्बाध डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) में एकीकृत करने के हमारे प्रयासों ने नए आयाम स्थापित किए हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष मंत्रालय ने देशभर में अपने व्यापक नेटवर्क में उन्नत पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (PSP V2.0) को सफलतापूर्वक लागू किया। इसके साथ ही, हमने विश्वभर में स्थित अपने राजनयिक मिशनों एवं केंद्रों में वैश्विक पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (GPSP V2.0) को लागू कर भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और सुविधा को और सुदृढ़ किया है। यह एकीकृत डिजिटल अवसंरचना सुनिश्चित करती है कि देश के भीतर के आवेदकों तथा विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों, दोनों को अत्याधुनिक डिजिटल सेवाओं का लाभ प्राप्त हो।

इस तकनीकी परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि चिप-युक्त ई-पासपोर्ट का सफल क्रियान्वयन है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ये यात्रा दस्तावेज हमारे नागरिकों के लिए सुरक्षा और प्रमाणीकरण को और मजबूत बनाते हैं। डिजिटल जैसी प्रणालियों के साथ सुरक्षित एकीकरण तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग से हम आवेदन प्रक्रिया को अधिक तीव्र, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बना रहे हैं।

हम 545 से अधिक पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSKs) और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSKs) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से अपनी अवसंरचना का निरंतर विस्तार कर रहे हैं। पासपोर्ट मोबाइल वैन की तैनाती के साथ हम अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इससे देश के दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक विश्वसनीय, लचीली और सुविधाजनक सेवाएँ पहुँच रही हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2013-14 में जारी किए गए 83 लाख पासपोर्ट की तुलना में, वित्त वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 138 लाख से ज्यादा हो गई है। यह वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहे भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मैं इस अवसर पर मंत्रालय तथा केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के समर्पित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अथक प्रयासों एवं पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी सहयोगियों—डाक विभाग, पुलिस प्राधिकरण, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक तथा अन्य सेवा प्रदाताओं के सतत योगदान की प्रशंसा करता हूँ।

आइए, आज हम "सुरक्षित पासपोर्ट, सुगम सेवा, सशक्त नागरिक" के मार्गदर्शक सिद्धांत के प्रति स्वयं को पुनः समर्पित करें। आइए, हम नवाचार को बढ़ावा देने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा वितरण में वैश्विक मानक स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संकल्प लें।

  
(डॉ. सु. जयशंकर)

जून 24, 2026